औद्योगिक जिला बनेगा लखनऊ

छह महीने में 10 हजार निर्माण इकाइयां ग्रामीण इलाकों में लगाने की तैयारी, वन स्टॉप सेंटर पर मिलेंगी सभी सहूलियतें

माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। यूपी की इकोनॉमी वन ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए लखनऊ प्रदेश का पहला औद्योगिक जिला बनेगा। इसके लिए यहां के ग्रामीण इलाकों में 10 हजार निर्माण इकाइयां अगले छह महीने में खोली जाएंगी। इनमें करीब पांच लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। शुक्रवार को डीएम के प्रस्ताव पर इसकी कार्ययोजना को अपर मुख्य सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल ने सहमति दे दी। इससे निर्माण इकाइयों के लिए निवेशकों को सब्सिडी का भी रास्ता खुल गया है।

डीएम सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि 10 लाख से लेकर एक करोड़ रुपये तक के निवेश की निर्माण इकाइयां लगाई जाएंगी। लखनऊ को औद्योगिक जिला बनाने के लिए ये इकाइयां प्रेरक बनेंगी। वर्ष 2024 के आखिरी तक इन्हें 50 हजार किया जाएगा। वहीं, अपर मुख्य सचिव की सहमति के बाद अब अलग-अलग योजनाओं में सरकार से मिलने वाली सब्सिडी दी जा सकेगी। यह पुरुष निवेशक के लिए 25 और महिला के लिए 35 प्रतिशत तक हो सकती है।

डीएम ने कहा कि अब जरूरत एक वन स्टॉप सेंटर की है, जहां ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्माण इकाई लगाने के इच्छुक को सभी जरूरी अनुमति, तकनीकी-वित्तीय जानकारियां एक ही जगह पर दी जा सकें। यहां बैंक, प्रशासन, उद्योग, लेसा आदि से जुड़े अधिकारी तैनात रहेंगे। जिला प्रशासन खुद इसकी निगरानी करेगा। सेंटर पर जरूरी प्रशिक्षण, बिक्री व विपणन के लिए तकनीकी सहयोग दिया जा सकेगा। बताया कि 10 हजार निर्माण इकाइयां लगाने के लिए करीब पांच हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा। इससे करीब पांच लाख रोजगार सृजित होंगे। डीएम का कहना है कि भले ही अभी सर्विस सेक्टर लुभावना लगे, लेकिन आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के लिए निर्माण इकाइयां ही जरूरी हैं। वहीं, इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय भी बढ़ेगी। यह भी कहा, बड़े कारोबारी और डिफेंस कॉरिडोर से जुड़ी कंपनियों को भी अभियान से जोड़ने की योजना है।

बड़े कारोबारी और डिफेंस कॉरिडोर से जुड़ी कंपनियों को भी अभियान से जोड़ने की योजना

05 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

5,000 करोड़ का होगा निवेश

25% सब्सिडी पुरुष निवेशक को

35% तक अनुदान महिलाओं को

हर गांव में 15 यूनिट का लक्ष्य : डीएम ने बताया कि लखनऊ में करीब 1000 राजस्व गांव हैं। कार्ययोजना यह है कि हर गांव में 15 निर्माण इकाइयां लगाई जाएं। इनमें कम से कम 10 इकाइयां ऐसी सुनिश्चित करनी हैं, जो चलें। बताया कि ग्रामीण इलाकों में अधिकतर लोगों के पास अपनी बिल्डिंग है। वहीं, ऐसी इकाइयां घर के अंदर भी चल सकती हैं। इससे स्थानीय लोगों को ही निर्माता बनाने के लिए सहयोग मिलेगा।

बीकेटी में शुरू होगी पहली इकाई

पहली निर्माण इकाई बीकेटी तहसील के लुधौली गांव में शुरू होगी। इसके लिए डीएम ने पिछले दिनों किसानों संग पंचायत भवन में एक बैठक भी की थी। यहां अधिकतर किसान केले की खेती करते हैं। ऐसे में केले के चिप्स आदि बनाने की इकाई शुरू करने पर सहमति बनी। कार्ययोजना के लिए डीएम ने ग्रामीण इलाकों के दौरे कर लोगों से रायशुमारी की थी।

...पर ये चुनौतियां भी हैं

- बड़ी संख्या में प्रशिक्षित मैनपावर निर्माण इकाइयों में उपलब्ध कराना।
- निर्माण इकाइयों को काम करने के लिए ऑर्डर चाहिए, जो दिलाना एक चुनौती है।
- बिना ऑर्डर के बने उत्पादों का विपणन व बिक्री नेटवर्क तैयार करना।
- निवेश के अलावा मशीन, जगह के अलावा जरूरी एनओसी की प्रक्रिया भी आसान नहीं होगी।

(एमएसएमई सेक्टर से जुड़े उद्यमी के मुताबिक)